(ii) INADEQUATE OFF-TAKE OF PADDY AT SUPPORT PRICES

SHRI P. RAJAGOPAL (Chittoor): Mr. Chairman, Sir, though the Government fixed a price of Rs. 105 a quintal of paddy, in many parts of the country it is not sold at that rate. For example, there are no buyers in Muzaffarnagar and Sultanpur in U.P. to buy paddy even at a price of Rs. 92 a quintal. This is quite unfortunate and distressing.

The Government and the FCI are not able to cope up with the ever-increasing production of paddy. It will even increase with the increase of irrigation and better research results.

It is not that there is no demand for rice. There is an ever-increasing demand for it in foreign countries. We are not planning properly for the utilisation of surplus foodgrains, especially rice. We are not making proper arrangements for storing, milling and procuring them. We are not providing enough money to purchase them.

Unless there is a legislation for compulsory purchase of surplus agricultural commodities for which support prices are published, there will be no use of publishing them. They will be only on paper without any use for the farmers.

(iii) STEPS TO PROVIDE ELECTRICTY TO FARMERS IN UTTAR PRADESH

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश इस समय बिजली के गम्भीर संकट मे गुजर रहा है। बिजली न मिलने के कारण प्रदेश में रबी के बुवाई-अभियान को गहरा धक्का लगा है। वैसे तो उत्तर प्रदेश की सरकार छः घंटे किसानों को बिजली देने की बात कहती है, परन्तु वास्तव में उन्हें दो-तीन घन्टे से अधिक बिजली नहीं मिलती। पिछले वर्ष के भयंकर सूखे और इस वर्ष के बाढ़ के प्रकोप के कारण किसानों की कमर टूट चुकी है। यदि इस वर्ष भी बुआई और सिचाई के लिए आवश्यक मात्रा में बिजली उपलब्ध नही करायी गई, तो वहां के किसानों की आर्थिक शक्ति समाप्त-प्राय: हो जायेगी।

केन्द्रीय सरकार और विशेषकर ऊर्जा मंत्री से मेरा निवेदन है कि इस संकट के समय वे उत्तर प्रदेश की तरफ सहायता का हाथ बढ़ायें। केन्द्रीय तथा अन्य स्रोतों से उत्तर प्रदेश को उसकी आवश्यकतानुसार तत्काल बिजली उपलब्ध कराई जाये तथा वहां बिजली का संकट समाप्त कराने के लिए कारगर कदम उठाये जायें।

(iv) NEED TO ALLOT RAILWAY WAGONS IMMEDIATELY TO CARRY FERTILIZERS TO BIHAR FROM PORTS

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, इस वर्ष बिहार में धान की फसल गत वर्ष की तुलना में अच्छी है। फिर भी हथिया नक्षत्र में वर्षा न होने के कारण धान की फसल को क्षति उठानी पडी है। जगह जगह पानी के अभाव मे धान का मारा पडा है। साथ ही जमीन में नमी के अभाव मे रबी की फसल की बुआई में भी कठिनाई हुई है। बिजली के अभाव में किसान नलकूपो का भी इस्तेमाल नही कर सके।

रबी की फसल अच्छी हो, इसके लिए पानी और खाद दोनों की आवश्यकता है। इस लिए बिहार सरकार ने भारत सरकार से एक अत्यावश्यक पत्र (एस० ओ० एस०) के द्वारा अनुरोध किया है कि हल्दिया, पारादीप, मद्रास और बम्बई की बंदरगाहों से 60 हजार मीट्रिक टन खाद की ढुलाई

के लिए रेल डिब्बों का विशष प्रबन्ध करे। राज्य सरकार का कहना है कि अगर अगले तीन सप्ताह के भीतर राज्य के विभिन्न जिलों में खाद नहीं पहुंचाई गई, तो फिर बाद में भेजने से कोई लाभ नहीं होगा और रबी की फसल मारी जायेगी।

रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस ओर शीघ्र ध्यान दे कर खाद की ढुलाई के लिए बिहार को आवश्यक रेल डिब्बों का आवंटन करने की व्यवस्था कर।

(v) MEASURES TO CONTAIN OUT-BREAK OF "ENCEPHALLITIS" IN CERTAIN TOWNS OF U.P. AND RELIEF TO THE VICTIMS

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सभापति महोदय, सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ आदि जिलों में मस्तिष्क ज्वर का व्यापक प्रकोप हो गया है। लगभग दो हजार से अधिक व्यक्ति इस भयंकर बीमारी में काल-कवलित हो गये। सब से आश्चर्य की बात है कि गत वर्ष भी यह बीमारी फैली थी और लगभग 800 आदमियों की मृत्यु हो गई थी। इस वर्ष सरकार ने समाचार-पत्रों के माध्यम से बड़ा आकर्षक बयान दिया, किन्तु मौके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। केन्द्र तथा राज्य के उच्च स्वास्थ्य अधिकारियों ने मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित स्थानों का कोई दौरा नहीं किया। यहां आदमी परेशान हैं, भयभीत हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि वह इस बीमारी से कैसे बचेगा या अभी तो वह जिन्दा है, अगले घंटे वह जिन्दा रहेगा या नहीं।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर ले जाते हुए जोरदार शब्दों में यह मांग करता हूं कि सरकार अविलम्ब मस्तिष्क ज्वर से मरे हुए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का 50,000 रुपये मुआवजा दे एवं मस्तिष्क ज्वर रोकने की दिशा में अविलम्ब महत्वपूर्ण कार्रवाई करे।

(vi) NEED FOR SETTING UP OF A PAPER MANUFACTURING FACTORY IN PILIBHIT DISTRICT OF U.P.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला उद्योगों की दृष्टि से शून्य है। प्रदेश सरकार ने इसे नोटीफाइड बैकवर्ड एरिया घोषित किया हुआ है। बनों की अधिकता होने के कारण तथा धान का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र होने के कारण यह जिला कागज उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जिला उद्योग प्रबन्धक तथा अन्य अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में कुछ प्रयत्न भी किया है तथा स्थान के निमित्त सर्वेक्षण की कार्यवाही भी की गई है। प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जिले को प्रोत्साहन देने के लिए कच्चे माल का बहुत बड़ा भंडार होते हुए यहां सार्वजनिक क्षेत्र में एक कागज की फैक्टरी की स्थापना के लिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं जिससे कुछ लोगों की बेरोजगारी भी दूर हो सके।

16.30 hrs.

SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY, TRIVANDRUM, BILL

MR. CHAIRMAN: I have received this letter from Shri Shivraj V. Patil:

"Sir,...

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): That is not required. It is enough you give the permission.